



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 329]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

प्रकरण सं. एस एस आर -09/2018

विषय – चीन जन. गण. से डकटाइल आयरन पाइपों के आयातों से संबंधित निणायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा.सं. 7/18/2018-डीजीएडी. :- यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए, चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "डकटाइल आयरन पाइपों" (जिसे आगे डीआई पाइप या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 04.09.2013 के अपने अंतिम जाँच परिणाम सं. 15/1006/2012-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2013 की अधिसूचना सं. 23/2013-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा शुल्क लगाया गया था।

2. और यतः मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड (ईसीएल), श्रीकालाहस्ती पाइप्स लि. (एसपीएल) और मै. जिंदल सॉ लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) द्वारा संयुक्त रूप से अधिनियम और नियमों के अनुसार एक याचिका दायर की गई है जिसमें चीन के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप लगाते हुए शुल्क की अवधि को आगे पांच वर्षों के लिए बढ़ाने हेतु डीआई पाइपों के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निणायक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

3. और यतः, घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका की जाँच के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि चीन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डीआई पाइपों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, निर्णायक समीक्षा की याचिका के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय की सूचना देते हुए दिनांक 17.05.2018 का आदेश जारी किया गया था।

4. और यतः उक्त आदेश के विरुद्ध घरेलू उद्योग ने अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष सिविल आवेदन सं. 2018 का 12368 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.9.2018 के अपने आदेश द्वारा उक्त याचिका का निपटान किया। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय से दिनांक 26.09.2018 के निदेशों के उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं :

"तदनुसार, दिनांक 17.05.2018 का विवादित आदेश अलग किया गया क्योंकि वह बिना किसी कारण के था। प्रतिवादी प्राधिकारी निर्णायक समीक्षा के आवेदन पर इस आदेश की प्राप्ति की तारीख के छह महीनों के भीतर कानून के अनुसार पुनः निर्णय लेंगे। वह निर्णय होने तक, पाटनरोधी शुल्क जिसकी अवधि 9.10.2018 को समाप्त होने वाली है, की अवधि बढ़ाई जाती है। तदनुसार याचिका की अनुमति दी जाती है। नियम निरपेक्ष हैं। सीधी सेवा की अनुमति है।"

5. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26.09.2018 के उक्त आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करते हैं।

क. विचाराधीन उत्पाद

6. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण से "सभी व्यासों के डकटाइल आयरन पाइप" हैं जिन्हें आम तौर पर डीआई पाइपों (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के रूप में जाना जाता है।

7. संबद्ध वस्तु को अध्याय शीर्ष 73030030 और 73030090 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है, यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। यह भी नोट किया जाए कि यह एक निर्णायक समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जाँच में यथा परिभाषित के अनुसार ही रहेगा।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध मै. इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लिमिटेड (ईसीएल), श्रीकालाहस्ती पाइप्स लि.(एसपीएल) और मै. जिंदल सॉ लि. द्वारा किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से देखा जा सकता है कि आवेदकों का उत्पादन भारत में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि वे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना जाता है और आवेदक भागीदार कंपनियों को क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग माना गया है।

ग. संबद्ध देश

9. इस जाँच में शामिल देश चीन जन. गण है।

घ. प्रक्रिया

10. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ङ जांच अवधि (पीओआई)

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि जनवरी 2017 से दिसम्बर, 2017 तक की है। क्षति जाँच अवधि में 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 और जाँच अवधि शामिल होगी।

च. सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना से प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
चौथा तल जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

13. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

छ. समय-सीमा

14. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की सूचना देने वाली इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

ज. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

16. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितवद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितवद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

17. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अन्तर्दृष्टि कर सकते हैं।

20. किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

झ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितवद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ञ. असहयोग

22. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

संजय चड्ढा, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 9th October, 2018
Case No. SSR- 09/2018

Subject: Initiation of Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Ductile Iron Pipes from China PR.

F.No.7/18/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Ductile Iron Pipes", (hereinafter also referred to as DI Pipes or subject goods) originating in or exported from China (hereinafter referred to as subject country). The Authority vide its final findings No.15/1006/2012-DGAD, dated 4.9.2013 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the subject country. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 23/2013—Customs (ADD), dated 10.10.2013.

2. And whereas, a petition was jointly filed by M/s Electrosteel Casting Limited (ECL), Srialahasti Pipes Limited (SPL) and M/s Jindal Saw Limited (hereinafter referred to as 'petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of "DI Pipes" for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China.

3. And whereas, based on examination of the petition filed by the Domestic Industry, Authority came to the conclusion that there was no need to initiate the Sunset Review concerning imports of DI Pipes originating in or exported from China and accordingly, order dated 17.05.2018 was issued intimating the decision of the Authority on Sunset Review petition.

4. And whereas against the said order, the Domestic Industry filed Special Civil Applications No. 12368 of 2018 before the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad. The Hon'ble High Court disposed of the said petition vide its order dated 26.9.2018. The extracts of direction dated 26.09.2018 from Hon'ble High Court of Gujarat are reproduced as under

“Accordingly, impugned order dated 17.05.2018 is set aside, as the same is without reasons. The respondent authority shall decide the application requesting a sunset review afresh, in accordance with law, within six months from the date of receipt of this order. Till such a decision is taken, the period of anti-dumping duty, which ceases to have effect on and from 9/10/2018, shall stand extended. Petition is allowed accordingly. Rule is made absolute. Direct service is permitted.”

5. Pursuant to the said orders of the Hon'ble High Court of Gujarat dated 26.09.2018 the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance with section 9A (5) of the Custom Tariff Amendment) Act read with Rule 23 of Antidumping Rules.

A. Product under Consideration

6. The product under consideration in the present application is “Ductile Iron Pipes of all diameters” commonly known as DI Pipes (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”) from China PR.

7. The subject goods are classified under chapter heading 73030030 and 73030090, it is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope. It is also noted that being a sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation.

B. Domestic Industry & Standing

8. The request for the sunset review has been filed by M/s Electrosteel Casting Limited (ECL), Srikalahasti Pipes Limited (SPL) and M/s Jindal Saw Limited. It is seen from the information on record that the production by the applicants account for a major proportion in the production of the subject goods by the domestic industry in India. Further, the applicants have submitted that they are not related to a producer/exporter of the product under consideration in subject countries or an importer in India. The application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the applicant participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules for the purpose of injury investigation.

C. Subject Country

9. The country involved in this investigation is China PR.

D. Procedure

10. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

E. Period of Investigation (POI)

11. The period of investigation for the purpose of the present investigations is January 2017 to December, 2017. The injury investigation period shall cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.

F. Submission of information

12. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi -110001.**

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

G. Time Limit

14. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-Dumping

measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

H. Submission of Information on Non-Confidential basis

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

I. Inspection of Public File

21. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

J. Non-Cooperation

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SANJAY CHADHA, Addl. Secy. & Director General